

Commr. (Pig) - II  
Despatch No. 652  
Date 24/07/12

R&D CELL  
VIKAS SADAN

VC

153

बु.वि. / 376297 / 2011 / सुझाव पत्र / दि.वि.प्रा. / 166

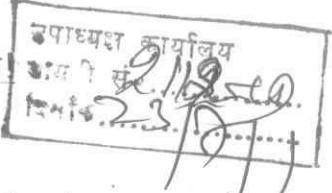
Dy. No. 3925 Date 23/7/12

दिनांक 05/05/2012

सेवा में,  
उपाध्यक्ष महोदय,  
दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास संदर्भ:  
आई एन ए. नई दिल्ली: 110023.

प्रधानमंत्री का अधिकारी :  
ले. नं. 1991 राकेश कुमार,  
जी. 27, बुद्ध विहार, फेस. 1, दिल्ली: 110086  
मो: 9968241017/V

विषय:- दिल्ली मुख्य योजना 2021 में परिवर्तन करने परिवर्तन करने की अपील  
( Put the Suggestions Mid term Review MPD-2021 File )



आपके कार्यालय में बु.वि. / 376297 / 2011 / सुझाव पत्र / दि.वि.प्रा. / 291, दिनांक: 12/12/2011, एम जैन  
प्रीतम पुरा खुले मंच के 77 नं. के तहत संलग्न बु.वि. / 376297 / 2011 / सुझाव / दि.वि.प्रा. / 151, दिनांक:  
01/05/2012 को प्रेषित करने के बाद आपके कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में अब तक की गई कार्यालयी की कोई  
जानकारी नहीं दी गई है अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित पुनः सुझाव / स्मरण पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

1. राजधानी दिल्ली क्षेत्र की बकाया खेती वाली भूमि पर कंकरीट के जंगल ना बने ऐसी क्षेत्रों Director (Pig) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy. No. L-34  
2. सब डवीजन व छाटे प्लाटो / मकानों के नक्शे भी पास होने चाहिए।  
2.1 नक्शे को पास करवाते वक्त पुराने मकानों को पूरा ना तोड़ने का प्रावधान हो।  
3. जिन क्षेत्रों में मकानों के नक्शे पास नहीं हो सकते उन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त वास्तुकार के माध्यम से या नक्शे  
वाले मकानों की तर्ज पर मकानों को बनाने की छूट हो इस संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में व बिल्डिंग  
बाई ला में जरूरी बदलाव किये जाने की जरूरत है, ताकि गरीब आदमियों के मकानों को सिविक ऐजेन्सियों  
ना तोड़ पायें।  
4. राजधानी दिल्ली कि अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों के निवासियों / नियमित वोटों के  
अनाधिकृत मकान किस प्रकार नियमित हो ऐसी पालिसी बनायें या मौजूदा पालिसी जरूरी बदलाव किये जाने  
की जरूरत है।  
5. अनाधिकृत बस्तियों के निवासियों की दुकानों को मिश्रित श्रेणी में शामिल ना करके व्यवसायिक श्रेणी में शामिल  
करने की कृपा करें तथा मानव हानि रहित व्यापारों करने की छूट देने की कृपा करें।  
6. आम आदमी को राहत देने तथा सरकार की आषदनी बढ़ाने के लिए राजधानी दिल्ली सभी अनियमित बने  
मकानों में कुछ बदलाव करके नियमित करने का प्रावधान होना चाहिए।  
7. राजधानी दिल्ली सभी अनियमित व नियमित बने मकानों में कुछ बदलाव करके अपने ही मकानों में पार्किंग कि  
व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए, इस संदर्भ में द्वारा छोटी बड़ी गाड़ियों के उत्पादन में नियंत्रण हो  
यदि दि. वि. प्रा. चाहे तो सरकार को अति आवश्यक सलाह देने की कृपा करें।

पृष्ठ संख्या: 1.

25/07/2012 ADP 09/07/2012

8. नये बनने वाले मकानों की उच्चोई में निम्न तल पर पूरी पार्किंग को 15मी॰ की हाईट में शामिल ना करने की कृपा करें।
9. प्रोत्साहन राशि सहित 100 मीटर के प्लाटो में जल संरक्षण के उपायों को जरूरी करने का प्रावधान होना चाहिए।
10. राजधानी दिल्ली कि अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों तथा गैर दि॰वि॰प्रा॰ निर्भित दुकानों से रजि॰चार्ज, कनवर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज, व्यवसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर में केवल एक ही लेने की व्यक्ति हो।
11. भविष्य की राजधानी दिल्ली की परियोजनाओं के मध्यनजर सरकार/दि॰ वि॰ प्रा॰ के पास उतनी व्यवसायिक भुखण्ड/दुकानें/इकायियों हैं जो आज का मास्टर प्लान-2021 को पूर्णतय लागू करने से बन्द होगी इस संदर्भ में दिल्लीवासियों जीवन यापन के लिए सभी अल्पआय व अति अल्पआय वर्गों की आर्थिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए मकान मालिक द्वारा संवयउपयोग हेतु रिहायशी व भिश्रित श्रेणी को व्यवसायिक लैड यूज बदलने की आसान प्रक्रिया का प्रावधान भी होना चाहिए।
12. फ्री होल्ड दि॰वि॰प्रा॰ निर्भित सिर्फ वह दुकानें जिनकी छते नालीदार सीमेटं कि चादरों की व गोलाईनुमा हैं उन्हें आर॰सी॰सी॰ की सीधी छत/सीधी स्लैब डालने की छूट का प्रावधान हो।
13. सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए ली नीजि भूमि जिनका कब्जा पिछले 20 साल से सिविक ऐजेन्सियों के पास नहीं है ऐसी भूमि का ना तो जमीदार व कब्जा धारक ने खुले बाजार भाव से मुआवजा नहीं लिया और ना ही विकल्पिक प्लाट लिया हैं ऐसी भूमि के नक्शे पास करने का प्रावधान होना चाहिए।
14. सिविक ऐजेन्सियों तथा दूसरे सरकारी निकाय पुनःअवलोकित मास्टर प्लान-2021 दुर्पयोग कर अनाधिकृत व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों राजधानी दिल्लीवासियों/नियमित वोट को दुखी ना कर सकें।
15. दि॰वि॰प्रा॰ द्वारा सभी छोटे बड़े नीजि बिल्डर्स का रजि॰ कर इनकी कार्यप्रणाली तथा इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाला मटिरियल की नियमित जाँच का प्रावधान होना चाहिए।
16. एस॰सी./एस॰टी./ अल्पसख्यक व अन्यों की तरह आर्थिक व अन्य पिछड़ेवर्गों को राजधानी दिल्ली में सस्ते व किश्तों में मकान व भुखण्ड/दुकानें/इकायियों देने का प्रावधान जिससे सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर हो सकें।
17. राजधानी दिल्ली की सभी सड़कों व संकीर्ण गलियों से छोटे-बड़ी गाड़ियों हटवाने का प्रावधान होना चाहिए।

पृष्ठ संख्या: 2.